भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1459

12 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: खरीद मानदंडों में छूट दिया जाना

1459. श्री बी पार्थसारधी रेड्डी

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बेमौसम वर्षा तथा मोथा चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान के मद्देनज़र तेलंगाना सरकार से सोयाबीन, मक्का और कपास के लिए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मांगी गई छूटों का फ़सल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छूट दिए गए मानदंडों के अंतर्गत खरीद की अनुमति देने संबंधी मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) तथा भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) के साथ परामर्श/विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) प्रभावित जिलों में एमएसपी प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा किसानों की परेशानी दूर करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): तेलंगाना सरकार से सोयाबीन और कपास के लिए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सोयाबीन के संबंध में, विजातीय पदार्थों और अशुद्धियों की अधिकतम सहनशीलता सीमा (प्रति क्विंटल भार के अनुसार) में 5% तक, सिकुड़े हुए अपरिपक्व दानों और रंग बदले हुए (डिस्कलर्ड) दानों में 10% तक तथा क्षतिग्रस्त एवं घुन लगे दानों में 10% तक की छूट मांगी गई है, जबकि निर्धारित अधिकतम सहनशीलता सीमा क्रमशः 2%, 5% और 3% है। कपास के मामले में, तेलंगाना सरकार ने 12% से अधिक और 18% तक नमी की मात्रा वाले कपास की एमएसपी पर खरीद की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

(ग): भारत सरकार केवल अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। अतः, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत इन फसलों की एमएसपी पर खरीद का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ): किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय नोडल एजेंसियां (सीएनए) किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोलती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि सभी पंजीकृत किसानों को सरकारी एमएसपी खरीद का लाभ सुनिश्चित हो सके।

*****